शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 50 वां वर्ष

ई-पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/shailsamachar

वर्ष 50 अंक-26 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 23-30 जून 2025 मूल्य पांच रूपये

क्या यह टनों के हिसाब से बही लकड़ी बारिश में ऊपर से बरसी है?

➪ सरकार की इस पर चुप्पी से उठे सवाल

➪ 2023 में थुनाग में भी ऐसे ही बही थी लकड़ी जिसका आज तक पता नहीं चला है।

शिमला/शैल। क्या हिमाचल में हर बरसात में ऐसे ही जान माल का नुकसान होता रहेगा? यह सवाल इसलिये उठ रहा है क्योंकि 2023 में भी आयी आपदा के दौरान मण्डी के थुनाग में आयी बाढ़ में बड़ी मात्रा में लकड़ी नालों में बहकर आयी थी। इस बार भी सैंज में बादल फटने से जीवा नाला में आयी बाढ़ में टनों के हिसाब से लकड़ी बहकर पंडोह डैम तक पहुंची है। सैंज में जहां बादल फटा है उस क्षेत्र में एक पॉवर प्रोजेक्ट का काम चल रहा था। यह काम एक इंदिरा प्रियदर्शनी कंपनी के पास है और कंपनी के पास सैकड़ो मजदूर काम कर रहे थे। पॉवर प्रोजेक्ट के काम में कई अनियमितताओं के आरोप लगे हैं जो जांच के बाद ही सामने आ पायेंगे। मजदूरों के पंजीकरण का भी आरोप है इसलिये मौतों के सही आंकड़ों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कांगड़ा के धर्मशाला में भी बादल फटने से बाढ़ आयी है जिसमें कई मजदूर बह गये हैं। इस क्षेत्र में भी सोकनी दा कोट में एक पॉवर प्रोजेक्ट का काम चल रहा था जिसके निर्माण में कई अनियमितताओं के आरोप हैं। 2023 में जब बरसात में आपदा आयी थी तब नदियों के किनारे हो रहे खनन को इसका बड़ा कारण बनाया गया था। इस पर मंत्रियों में ही विवाद भी हो गया था। इस समय हिमाचल में चंबा से लेकर किन्नौर शिमला तक करीब साढे पांच सौ छोटी-बड़ी पॉवर परियोजनाएं चिन्हित हैं और अधिकांश पर काम चल रहा है। चंबा में रावी पर चल रही पॉवर परियोजनाओं में 65 किलोमीटर तक रावी अपने मूल बहाव से लोप है। यह तथ्य अवय शुक्ला की रिपोर्ट में दर्ज है और प्रदेश उच्च न्यायालय में यह रिपोर्ट दायर है। स्वाभाविक है कि जब पानी के मूल रास्ते को रोक दिया जायेगा तो बरसात की किसी भी बारिश में जब पानी बढ़ेगा तो वह तबाही करेगा ही। अवय शुक्ला की रिपोर्ट का संज्ञान लेकर पॉवर परियोजनाओं में इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं इसको लेकर कोई रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आ पायी है। पॉवर परियोजनाओं के निर्माण से पूरे क्षेत्र का पर्यावरण संतुलन प्रभावित हुआ है और इसका असर ग्लेशियरों के पिघलने पर पढ़ रहा है। लाहौल-स्पीति और किन्नौर में कई परियोजनाओं पर स्थानीय लोगों ने आपत्तियां भी उठाई है और धरने प्रदर्शन भी किये हैं। ग्लेशियरों के पिघलने से कालान्तर में परियोजनाओं पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिये समय रहते इस सवाल पर ईमानदारी से विचार करके कुछ ठोस और दीर्घकालिक उपाय करने होंगे अन्यथा भविष्य में और भी गंभीर स्थितियों का सामना करना पड़ेगा।

2023 में जो लकड़ी थुगान में बहकर आयी थी उसका संज्ञान शायद अदालत ने भी लिया था और उस पर एक रिपोर्ट भी तलब की थी। इस रिपोर्ट में क्या सामने आया है इसको लेकर कोई जानकारी आज तक सामने नहीं आयी है। न ही किसी ने यह दावा किया है कि यह लकड़ी उसकी थी। उस अवैधता पर आज तक पर्दा पड़ा हुआ है। अब सैंज में बादल फटने से जो लकड़ी जीवा नाला से होकर पंडोह तक पहुंची है उसको लेकर भी रहस्य बना हुआ है कि यह लकड़ी किसकी है। टनों के हिसाब से पंडोह डैम में लकड़ी पहुंची है। वन निगम जिसके माध्यम से वन विभाग लकड़ी का निस्तारण करता है उसके उपाध्यक्ष ने साफ कहा है कि यह लकड़ी वन निगम की नहीं है। क्षेत्र के वन विभाग के अधिकारियों ने भी इस लकड़ी के बारे में स्पष्ट कुछ नहीं कहा है इसे बालन की लकड़ी कहकर पल्ला झाड़ने का प्रयास किया है। इस लकड़ी के जो वीडियो सामने आये हैं उनसे स्पष्ट हो जाता है कि यह करोड़ों की लकड़ी है। यदि किसी प्राइवेट आदमी की इतनी मात्रा में वैध लकड़ी इस तरह बह जाती तो वह तो तूफान खड़ा कर देता। परन्तु ऐसा भी कुछ सामने नहीं आया है। टनों के हिसाब से लकड़ी सामने है लेकिन इसका मालिक कोई नहीं है। सरकार के वन विभाग का लकड़ी के निस्तारण का काम वन विभाग के माध्यम से होता है और वन विभाग लकड़ी का मालिक होने से इन्कार कर रहा है तो स्वाभाविक है कि यह लकड़ी अवैध कटान की ही है क्योंकि बारिश में आसमान से तो यह टपकी नहीं है? सरकार ने अभी तक इस लकड़ी का स्रोत पता लगाने के लिये कोई कदम नहीं उठाये हैं इस बारे में कोई जांच गठित नहीं की गयी है। वन विभाग का प्रभार स्वयं मुख्यमंत्री के पास है। सरकार में किसी मंत्री ने इस पर कोई सवाल नहीं उठाया है। केवल अखिल भारतीय कांग्रेस प्रवक्ता विधायक कुलदीप राठौर ने इसकी जांच किये जाने की मांग की है। सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से इस पर कुछ न कहने से और भी कई सवाल खड़े हो जाते हैं। यहां तक पॉवर प्रोजेक्ट का निर्माण कर रही कंपनी तक सवाल उठने लग पड़े हैं।

आपदा की स्थिति से निपटने के हों पूरे इंतजाम:जयराम ठाकुर

शिमला/शैल। शिमला से जारी बयान में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में ज्यादातर जगहों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग द्वारा कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में प्रदेश के लोगों से मेरी गुजारिश है कि वह एहतियात बरतें। अनावश्यक यात्राओं से बचें। अपना और अपने परिवार का बेहद ख्याल रखें। नदी नालों से दूर रहे और प्रशासन द्वारा चिन्हित किए गए खतरनाक स्थानों पर न जाएं। सुरक्षित स्थानों पर रहें। साथ ही सरकार से निवेदन है कि आपदा राहत और बचाव की तैयारी के साथ ही आपदाओं से होने वाले जोखिम के न्यूनीकरण की दिशा में भी प्रभावी कदम उठाएं जिससे आपदा के दौरान नुकसान को न्यूनतम किया जा सके।

जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में मानसून की शुरुआत में ही भारी तबाही हुई है। नदी नालों के उफान और बादल फटने की घटनाओं के चलते कई लोगों की दुखद मृत्यु भी हो गई है। जन धन की भारी क्षति हुई है। प्रदेश भर में कई स्थानों पर अलग अलग तरह का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार आपदा राहत के लिए प्रशासन और सतर्कता बरते। प्रदेश का संपूर्ण आपदा राहत तंत्र अति सतर्कता बरते और सक्रियता दिखाए। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तैयारी रखे। जिससे किसी भी आपदा से आसानी से निपटा जा सके।

शेष पृष्ठ 8 पर......

केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यपाल के नशामुक्त अभियान को भरपूर सहयोग का आश्वासन दिया

शिमला/शैल। केंद्रीय श्रम, रोजगार तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भेंट की। इस अवसर पर सांसद एन. के. प्रेम चंद तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी के सदस्य भी उनके साथ उपस्थित थे।

केंद्रीय मंत्री ने श्रमिक कल्याण योजनाओं तथा राज्यपाल द्वारा संचालित राज्यव्यापी नशामुक्ति अभियान की प्रगति को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की। उन्होंने राज्यपाल को शॉल, टोपी और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।

राज्यपाल ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में चल रहे नशामुक्त अभियान की संरचना बहुस्तरीय है जो अब पंचायत स्तर तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ जागरूकता की दिशा में अब जनप्रतिनिधि भी सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं।

राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से आरम्भ यह

अभियान अब एक जन आन्दोलन का रूप ले चुका है।

मांडविया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को राज्यपाल शुक्ल के लम्बे राजनीतिक अनुभव का लाभ मिल रहा है। उन्होंने ने राज्यपाल को नशामुक्त अभियान में मंत्रालय द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया और कहा कि इनका मंत्रालय भी कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सक्रिय भागीदारी से नशा विरोधी अभियान आरम्भ करेगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को जागरूक करने के लिए हिमाचल के नशामुक्त मॉडल को पूरे देश में अपनाया जाएगा।

राज्यपाल ने वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिमला जिला के रामपुर स्थित ऐतिहासिक पदम पैलेस, में पूर्व

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की चौथी पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भाग लिया। राज्यपाल ने वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वह एक प्रखर राजनेता, दूरदर्शी नेतृत्वकर्ता और जनसेवा के प्रति समर्पित व्यक्तिव थे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सर्वांगीण विकास में वीरभद्र सिंह का योगदान सदैव स्मरण रहेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा।

राज्यपाल ने यह भी कहा कि वीरभद्र सिंह ने हिमाचल की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को सहेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने धर्मान्तरण पर रोक लगाने के लिए कानून बनाकर देवभूमि की पवित्रता और सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्धता का परिचय दिया। यह उनका राज्य के प्रति गहरे उत्तरदायित्व का प्रतीक था।

इस अवसर पर वीरभद्र सिंह के परिवारजन, गणमान्य व्यक्ति, स्थानीय नागरिक एवं अनेक शुभचिंतकों ने भी वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की।

सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक उत्सव व्यक्तित्व के विकास के लिए महत्वपूर्णः राज्यपाल

शिमला। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला स्थित अटल ऑडिटोरियम में राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल द्वारा आयोजित अंतर महाविद्यालय फेस्ट 'इरप्शन-2025 के समापन समारोह में भाग लिया।

समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा और संस्कृति एक-दूसरे को समृद्ध कर सकते हैं और 'इरप्शन' जैसे उत्सव इस तालमेल को मजबूत करने का एक सशक्त माध्यम हैं। उन्होंने इस तरह के जीवंत, रचनात्मक और प्रेरक कार्यक्रम के आयोजन के लिए कॉलेज प्रबंधन और छात्र परिषद को बधाई दी और छात्रों द्वारा प्रस्तुत की गई उत्कृष्ट सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की सराहना की।

राज्यपाल ने कहा कि सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से छात्रों ने न केवल शैक्षणिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, बल्कि अपने प्रदर्शन के माध्यम से 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की झलक भी दिखाई है। उन्होंने विद्यार्थियों की कला और सांस्कृतिक प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी विवेकाधीन कोष से 2 लाख रुपये देने की घोषणा की।

उन्होंने कहा, हिमाचल अपनी ईमानदारी और भोलेपन के लिए जाना

जाता है, जिसका असामाजिक तत्व लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। हमें इस मामले को गंभीरता से लेते हुए नशीली दवाओं के दुरुपयोग को खत्म करने के लिए एकजुट होना चाहिए। उन्होंने इस दिशा में योगदान के लिए आईजीएमसी में चिकित्सकों के संघ 'मेडीविजन' के समर्थन की भी सराहना की।

राज्यपाल ने मौखिक स्वास्थ्य देखभाल सेवा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 'मुस्कान एक वैश्विक भाषा है और यह देखकर खुशी होती है कि आप सभी अनगिनत चेहरों पर सच्ची मुस्कान लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।' उन्होंने राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, शिमला के योगदान की सराहना की, जिसने अपने स्थापना वर्ष 1994 से अब तक कुशल एवं दक्ष दंत चिकित्सक तैयार किए हैं।

इस अवसर पर राज्यपाल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विजेताओं को सम्मानित भी किया।

2015 के बाद होगी होमगार्ड की भर्ती

शिमला/शैल। राज्य सरकार द्वारा होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में 700 होमगार्ड की भर्ती की जा रही है। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हाल ही में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में इन पदों को भरने की मंजूरी दी है और वर्ष 2015 के बाद पहली बार होमगार्ड की भर्ती की जा रही है।

उन्होंने बताया कि भर्ती में लंबे समय से रुकावट के कारण न केवल कर्मियों की भारी कमी हुई है, बल्कि होमगार्ड की तैनाती के अनुरोध को विभाग मांग अनुरूप पूरा नहीं कर पा रहा है। आवश्यकता के समय प्रभावी एवं शीघ्र प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए नए होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती की आवश्यकता थी।

प्रवक्ता ने कहा कि सरकार का यह कदम राज्य के युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने में मददगार साबित होगा। प्रदेश में होमगार्ड स्वयंसेवकों की कुल संख्या 8000 है। होमगार्ड की कमी के कारण विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों आदि से प्राप्त हो रही उनकी तैनाती की मांग को विभाग पूरा नहीं कर पा रहा था।

उन्होंने कहा कि होमगार्ड विभिन्न कार्यों में पुलिस और नागरिक प्रशासन की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी जिम्मेदारियों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना, यातायात नियंत्रण, निर्वाचन ड्यूटी, त्योहारों और बड़ी सभाओं के दौरान भीड़ प्रबंधन इत्यादि शामिल हैं। अक्सर प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं और वनाग्नि के दौरान होमगार्ड प्रतिक्रिया देने में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। बहुमूल्य जीवन बचाने तथा व्यवस्था बहाल करने में मदद करते हैं। राज्य सरकार ने नए होमगार्ड स्वयंसेवकों के पारिश्रमिक और अन्य संबंधित लागतों के लिए 24 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। विभाग में जनशक्ति को मजबूत करके, राज्य सरकार का उद्देश्य इसकी क्षमताओं को बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना है कि यह राज्य भर में नागरिक सुरक्षा और सामुदायिक सुरक्षा की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए अच्छी तरह से तैयार रहें।

राज्यपाल ने 'नशे को मात, देंगे एक साथ' थीम पर आधारित 12वीं हाफ मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा आयोजित 12वीं हाफ मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस

मैराथन का 'नशे को मात, देंगे एक साथ' थीम पर आयोजन करवाया गया।

भारी बारिश के बावजूद मैराथन में भाग लेने वाले प्रतिभागियों, खासकर युवाओं की हौसला अफजाई करते हुए राज्यपाल ने कहा कि बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजन सहित सभी वर्गों के लोग इस मैराथन में भाग ले रहे हैं, जो नशे के खिलाफ सामूहिक भावना को प्रदर्शित कर रहा है।

राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के लोग हिमाचल को नशामुक्त राज्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि 'नशे को मात, देंगे एक साथ' अभियान की पहुंच हर घर तक सुनिश्चित की जानी चाहिए और उन्होंने इस अभियान के लिए पुलिस विभाग के प्रयासों की सराहना की।

इस अवसर पर राज्यपाल ने प्रतिभागियों को सभी प्रकार के नशीले पदार्थों से दूर रहने की शपथ दिलवाई।

शुक्ल ने राज्य पुलिस द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का शुभारम्भ किया तथा नशे के विरुद्ध अभियान के प्रति अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए 'हस्ताक्षर बोर्ड' पर हस्ताक्षर किए। मैराथन को चार श्रेणियों हाफ मैराथन, मिनी मैराथन, ड्रीम रन तथा दिव्यांग प्रतिभागियों के लिए विशेष दौड़ में विभाजित किया गया है। हाफ मैराथन के विजेता को 51,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

कामगार कल्याण बोर्ड ने बालीचौकी में उप-कार्यालय स्थापित करने की स्वीकृति दी

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर की अध्यक्षता में बोर्ड के निदेशक मण्डल की 49वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में बोर्ड से सम्बंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। इस अवसर पर बोर्ड ने अधिकारियों के माध्यम से पंचायत स्तर पर पंजीकृत श्रमिकों की ई-केवाईसी की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्णय लिया।

निदेशक मण्डल ने स्टाफ सहित जिला मण्डी के बालीचौकी में उप-कार्यालय स्थापित करने का भी निर्णय लिया।

नरदेव सिंह कंवर ने कहा कि बोर्ड आउटसोर्स सेवाओं के समझौते के मामले पर चर्चा कर इस मामले में एचपीएसईडीसी और आउटसोर्स एंजेंसी के साथ बैठक कर उचित निर्णय लेगा।

निदेशक मण्डल ने सरकारी वस्तुओं की खरीद के साथ-साथ विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार के लिए 2 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट को भी मंजूरी दी। इसके अलावा बोर्ड जिला स्तर पर 12 आउटडोर एलईडी और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के व्यापक प्रचार के लिए उचित मूल्य की दुकानों पर अस्थाई फ्लेक्स, होर्डिंग लगाए जाएंगे।

नरदेव सिंह ने बोर्ड के अधिकारियों को श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लाभ सुनिश्चित करने के लिए हर सम्भव प्रयास सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव कुमार ने भी बैठक के दौरान बोर्ड की बेहतरी और इसकी गतिविधियों को और प्रभावी तरीके से बढ़ाने के संदर्भ में अपने बहुमूल्य सुझाव दिए।

बोर्ड के सदस्य विजय वर्धन, भूपेंद्र सिंह, जे.सी चौहान, प्रदीप कुमार, मनीष करोल, ज्योति चौहान, अमर सिंह और नीलम गुप्ता ने बैठक में भाग लिया।

प्रदेश सरकार डेंटल पीजी डाक्टरों का स्टाइपेंड बढ़ायेगी

शिमला/शैल। ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने राजकीय डेंटल कॉलेज, शिमला में आयोजित इंटर कॉलेज समारोह 'रिशेप्शन-2025' की अध्यक्षता की।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने की दिशा में भी निरंतर कार्य कर रही है ताकि प्रदेशवासियों को राज्य में ही गुणवत्तायुक्त चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित हो सकें और ईलाज के लिए अन्य राज्यों में जाने की आवश्यकता न पड़े।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार चिकित्सा महाविद्यालयों के उन्नयन पर 1100 करोड़ खर्च कर रही है। यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि प्रदेश के एआईएमएसएस चमियाणा में पहली रोबोटिक सर्जरी मशीन स्थापित की गई है। इसी प्रकार राज्य के अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों में भी रोबोटिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आगामी तीन माह के भीतर प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में पैट स्कैन और 3-टेस्ला एमआर आई मशीनें स्थापित की जाएंगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने एमडी डाक्टरों का स्टाइपेंड 60 हजार रुपये से एक लाख रुपये कर दिया है

और सुपर स्पेशेयलिटी डॉक्टरों के स्टाइपंड में भी आशातीत बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि एमडी करने वाले डेंटल डॉक्टरों को स्टाइपंड भी इसी आधार पर बढ़ाया जाएगा।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम प्रतिभा प्रदर्शित करने और व्यक्तित्व विकास का अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि अनाथ बच्चों के लिए कानून बनाने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को 5 लाख रुपये की राशि देने की घोषणा की।

इस अवसर पर विधायक हरीश जनारथा, कॉलेज प्राचार्य डा. आशु भारती, कॉलेज स्टॉफ और विद्यार्थी उपस्थित थे।

स्वास्थ्य विभाग शीघ्र ही शुरू करेगा पैलिएटिव देखभाल अभियानः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पैलिएटिव देखभाल की आवश्यकता वाले गंभीर बीमारियों से पीड़ित पात्र लाभार्थियों

विशेषकर वृद्धजनों की पहचान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में शीघ्र पैलिएटिव देखभाल अभियान शुरू करेगी। इस अभियान का उद्देश्य वृद्धजनों एवं गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को घर-द्वार पर ही चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आशा कार्यकर्ता एवं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ पात्र लाभार्थियों की पहचान करेंगे और इसके उपरांत आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के चिकित्सा अधिकारी, फिजियोथेरेपिस्ट और सीएचओ की टीम घर जाकर चयनित लाभार्थियों की उपचार योजना तैयार करेंगे। यह पहचान एवं योजना प्रक्रिया अभियान के आरम्भ से तीन माह के भीतर पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में पैलिएटिव देखभाल के लिए विशेष केन्द्र स्थापित किए जाएंगे, जहां दो चिकित्सक, दो नर्सें, एक फिजियोथेरेपिस्ट तथा एक परामर्शदाता स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगे। यह टीम हर तीमाही में लाभार्थियों के घरों का दौरा कर उनकी निगरानी एवं आवश्यक सहायता प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री ने बैठक में हिमकेयर तथा आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा करते हुए लाभार्थियों को हिम परिवार नंबर से जोड़ने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नए हिमकेयर आवेदक तिमाही आधार पर योजना के तहत नामांकन के लिए आवेदन कर सकेंगे जिसके पश्चात उन्हें हिमकेयर कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल और मेडिकल सुपरिंटेंडेंट को अपने-अपने अस्पतालों में 100 गंभीर रोगियों के लिए हिमकेयर कार्ड जारी करने की सिफारिश करने का अधिकार भी दिया जाएगा।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 41.62 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 49 नए डायलिसिस केंद्र स्थापित करेगी।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने दिये मानसून में ज़िला प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश में मानसून के दौरान मौसम की विपरीत परिस्थितियों के दृष्टिगत सभी उपायुक्तों को सतर्क

रहने और आमजन के लिए 24x7 उपलब्ध रहने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। उन्होंने शिमला से वर्चुअल माध्यम से प्रदेश में मौसम की स्थिति की समीक्षा करते हुए सभी उपायुक्तों से आपदा प्रभावित लोगों के लिए राहत एवं पुनर्वास कार्य युद्धस्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नदी-नालों के निकट रह रहे लोगों विशेषकर प्रवासी मज़दूरों की पहचान करने और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर पुनर्वास करने को कहा। उन्होंने उपायुक्तों को पर्यटकों और स्थानीय लोगों को बारिश के मौसम में नदी-नालों के समीप नहीं जाने को लेकर एडवायज़री जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश में किसी भी प्रकार की क्षति की सूचना सरकार को शीघ्र उपलब्ध करवाने को कहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर वर्ष मॉनसून के कारण जल विद्युत परियोजनाओं को बार-बार नुकसान उठाना पड़ता है। इनकी सुरक्षा के लिए एक समग्र रणनीति बनाई जाए, जिससे इन परियोजनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश में तीन स्थानों पर बादल फटने, बाढ़ की नौ और भू-स्खलन की तीन घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें पांच लोगों की मृत्यु होने और एक व्यक्ति के घायल होने की पुष्टि की गई है। ज़िला कुल्लू में तीन और ज़िला कांगड़ा में पांच से छह लोग अभी भी लापता हैं जबकि फसे हुए 21 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग-505 और एनए-3 पर भूस्खलन पर अभी भी कई स्थानों पर मार्ग अवरुद्ध है। कुल्लू ज़िले में सैंज घाटी के मझान नाला में बादल फटने की घटना के बाद सैंज, पार्वती और लारजी जल विद्युत परियोजनाओं को हुए नुकसान के दृष्टिगत इन परियोजनाओं को बंद कर दिया गया है और गेट खोल दिए गए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में एसडीआरएफ, होमगार्ड और एनडीआरएफ की टीमें निरंतर राहत एवं बचाव कार्यों में जुटी हैं।

एनएएस-2025 में 5वें स्थान पर पहुंचा हिमाचल, 2021 में था 21वें स्थान पर

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। नवीनतम राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण एनएएस 2025, जिसे परख-2025 के रूप में भी जाना जाता है, ने हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर समग्र रैंकिंग में 5वें स्थान पर रखा है, जो पिछली भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान किए गए 2021 के सर्वेक्षण में 21वें स्थान से एक महत्वपूर्ण छलांग है।

सर्वेक्षण के अनुसार, हिमाचल प्रदेश ग्रेड-3 स्तर पर दूसरे स्थान पर, ग्रेड-6 पर 5वें और ग्रेड-9 पर चौथे स्थान पर रहा है, जो स्पष्ट रूप से राज्य की शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त गुणात्मक सुधारों को दर्शाता है।

यह उल्लेखनीय प्रगति मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखु के मार्गदर्शन में वर्तमान सरकार द्वारा शुरू किए गए केंद्रित सुधारों की एक श्रृंखला का परिणाम है। इनमें कम छात्र नामांकन वाले स्कूलों का विलय, शिक्षण स्टाफ का युक्तिकरण, रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाना और सभी विधानसभा क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना शामिल है।

इसके अलावा, शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों के एक्सपोजर दौरों ने वैश्विक शिक्षण दृष्टिकोण और समग्र शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने में योगदान दिया है। इन रणनीतिक कदमों से सीखने के परिणामों और समग्र शैक्षिक गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार आया है।

राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान राजेश शर्मा ने एनएएस-2025 में राज्य के प्रदर्शन को एक बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इस रैंकिंग के बारे में आधिकारिक घोषणा 2 जुलाई, 2025 को दिल्ली में की जाएगी, जहां वह राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने कहा कि यह परिणाम राज्य सरकार की सुसंगत और सुधार-संचालित नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम है। यह उपलब्धि देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक मॉडल के रूप में हिमाचल प्रदेश की बढ़ती स्थिति को रेखांकित करती है।

मुख्यमंत्री ने नगरोटा-बगवां में 36 करोड़ रुपये की विकासात्मक परियोजनाओं की सौगात दी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कांगड़ा ज़िला के नगरोटा-बगवां विधानसभा क्षेत्र के लिए 36 करोड़ रुपये लागत की आठ विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए।

मुख्यमंत्री ने नगरोटा-बगवां में 3.10 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित अग्निशमन केन्द्र भवन का उद्घाटन किया। इसके अलावा, 4. 80 करोड़ रुपये की लागत से मलां से गुजरेहड़ा- पठियार-सकरेहड़ सड़क, 4.84 करोड़ रुपये की लागत से खरट-जंदराह-ऐरला -रोपा -करडियाणा सड़क की मैटलिंग व टारिंग कार्य और धरुं खड्ड पर 3.47 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 33.40 मीटर पुल का शुभारम्भ किया जो कलेड को कराली दा बाग गांव को जोड़ेगा।

उन्होंने रंगेहड़-सदू-माल्मू से नेरा सड़क के निर्माण और नेरा खड्ड पर पुल तथा नगरोटा बगवां क्षेत्र के लिए 10 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न विद्युत अधोसंरचना विकास कार्यों की आधारशिला भी रखीं।

बांध सुरक्षा अधिनियम के तहत कड़ी से कड़ी कारवाई करें उपायुक्तःजगत सिंह नेगी

शिमला/शैल। राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जनशिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में मानसून को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति, बिजली बोर्ड, एसडीआरएफ, राजस्व व अन्यों विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

जगत सिंह नेगी ने सभी विभागों से वर्तमान स्थिति की जानकारी हासिल करने के साथ-साथ जिला स्तर पर तैयारियों को लेकर समीक्षा की।

बैठक में अवगत करवाया गया कि कांगड़ा, मंडी में भारी बारिश हो रही है और यहां हर तरह की पूरी तैयारी और मशीनरी तैनात की गई है। प्रदेश में बारिश-भूस्खलन के कारण बाधित 234 सड़कों को जल्द बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक सभी नेशनल हाईवे यातायात के लिए सुचारू हैं।

बिजली बोर्ड के 968 ट्रांसफॉर्मर प्रभावित हैं और बिजली बहाली के प्रयास जारी हैं। जलशक्ति विभाग की 23 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं जिन्हें शीघ्र बहाल किया जाएगा ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। रामपुर के सरपारा में बाढ़ की घटना हुई है लेकिन इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है।

जगत सिंह नेगी ने निर्देश दिए कि किसी भी क्षेत्र में घटना होने पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तुरंत प्रतिक्रिया दें। उन्होंने कहा कि मंडी, कुल्लू और कांगड़ा में बड़े बांध हैं, इसलिए तीनों जिलों के उपायुक्त कड़ी निगरानी रखें और नियमों की उल्लंघना पाये जाने पर बांध सुरक्षा अधिनियम (डैम सेफ्टी एक्ट) और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कड़ी से कड़ी कारवाई करें।

उन्होंने कहा कि मौसम विभाग की चेतावनी को मद्देनजर रखते हुए पर्यटक अपना गंतव्य चुनें और नदी-नालों के आसपास न जायें। वहीं सभी एसडीएम को भी सतर्क रहने के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

जगत सिंह नेगी ने कहा कि एसडीआरएफ को बजट जारी किया जा चुका है। इसलिए पूरी तैयारी के साथ मशीनरी को तैनात रखें।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत, निदेशक एवं विशेष सचिव आपदा प्रबंधन डीसी राणा, एसपी एसडीआरएफ अर्जित सेन ठाकुर, अतिरिक्त सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन निशांत ठाकुर, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग नरेंद्र पाल सिंह, प्रमुख अभियंता जल शक्ति विभाग अंजु शर्मा व वरिष्ठ निजी सचिव तुलसी राम शर्मा उपस्थित रहे।

काम की अधिकता नही, अनियमितता आदमी को मार डालती है। ......महात्मा गांधी

सम्पादकीय

चुनौती पूर्ण होगा डॉ. बिन्दल का अगला सफर

प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में डॉ. बिन्दल तीसरी बार भाजपा के अध्यक्ष बनना निश्चित रूप से एक बड़ी राजनीतिक सफलता है। क्योंकि भाजपा एक ऐसा राजनीतिक संगठन है जिसमें अध्यक्ष के लिये कभी भी मतदान की स्थिति नहीं आने दी जाती है। इसमें चयन नहीं मनोनयन का सूत्र प्रभावी होता है और यह मनोनयन राज्य ही नहीं बल्कि केन्द्रीय नेतृत्व से होकर आता है। इस समय प्रदेश में जिस तरह से भाजपा नेतृत्व कांग्रेस सरकार के साथ खड़ा नजर आ रहा है उसमें बिन्दल का अध्यक्ष बनना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हिमाचल की राजनीतिक परिपाटी में आगे भाजपा का सत्ता में आना लगभग तय माना जा रहा है। फिर हिमाचल में आज तक मुख्यमंत्री का पद राजपूत और ब्राह्मण समुदाय से बाहर नहीं गया है। आने वाले समय में भी यही दोहराये जाने की संभावना है। इसमें भी बिन्दल किसी के लिये चुनौती नहीं होंगे यह भी तय माना जा रहा है। इस समय हिमाचल एक कठिन वित्तीय दौर से गुजर रहा है। सरकार में आम आदमी पर जिस तरह से करों/शुल्कों का बोझ बढ़ाकर प्रदेश को कर्ज के चक्रव्यूह में डाल दिया है वह भविष्य की सरकारों के लिये भी एक समस्या बनेगी यह तय है। वर्तमान सरकार प्रदेश के वित्तीय संकट के लिये पूर्व भाजपा सरकार के कुप्रबंधन को लगातार दोषी ठहराती आ रही है। लेकिन भाजपा इस आरोप का कोई बड़ा जवाब नहीं दे पायी है। क्योंकि भाजपा पर यह आरोप भी आ गया है कि उसने धन बल के सहारे सरकार को गिराने का प्रयास किया और प्रदेश की जनता ने उपचुनाव में फिर कांग्रेस को उस बहुमत पर लाकर खड़ा कर दिया। भाजपा इसका भी कोई राजनीतिक जवाब अभी तक नहीं दे पायी है।

पिछले विधानसभा चुनावों में भाजपा की सरकार नहीं बन पायी क्योंकि हमीरपुर और शिमला संसदीय क्षेत्रों में पार्टी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही। जिस तरह का चुनाव परिणाम मण्डी ने भाजपा को दिया यदि वैसा ही परिणाम हमीरपुर, शिमला का भी रहता तो स्थितियां कुछ और ही होती। राज्यसभा चुनाव में जब भाजपा पर दल बदल करवा कर सरकार गिराने का आरोप लगा उसके बाद से भाजपा आज तक उस आरोप से न तो मुक्त हो पायी है और न ही सरकार को नुकसान पहुंचा पायी है। जबकि ऐसी परिस्थितियां विधानसभा उपचुनावों के दौरान ही निर्मित हो गयी थी कि भाजपा जब चाहे सरकार बदलवा सकती है। देहरा उपचुनाव में 78.50 लाख रुपया चुनाव के अन्तिम सप्ताह में सरकारी आदारों द्वारा कैश बांटा जाना एक ऐसा सवाल बन चुका है जिस पर भाजपा की चुप्पी कई कुछ कह जाती है। क्योंकि इस संबंध में राज्यपाल के पास आयी होशियार सिंह की शिकायत पर अभी तक कोई कारवाई न हो पाना कई सवालों को जन्म दे जाता है।

इसी तरह नादौन में हुई ई.डी. की छापेमारी में दो लोगों की गिरफ्तारी के बाद उस मामले में भी आगे कुछ न होना भी कई सवाल खड़े कर जाता है। अब विमल ने की मौत प्रकरण की जांच में सी.बी.आई. का अब तक खाली हाथ होना भी लोगों में सवाल खड़े करने लग पड़ा है। इन सवालों पर प्रदेश भाजपा का नेतृत्व लगभग मौन चल रहा है। बल्कि कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुये नेता भी अब लगभग शान्त होकर बैठ गये हैं। भाजपा शायद इस सोच में चल रही है कि वर्तमान सरकार जनता में जितनी असफल प्रमाणित होती जायेगी उसी अनुपात में उसका स्वभाविक लाभ भाजपा को मिल जायेगा। लेकिन जिस तरह से भाजपा में ही कुछ असन्तुष्ट नेताओं ने एक अलग गुट खड़ा कर लिया है उसमें यदि कल को कुछ और नेता भी जुड़ जाते हैं तो स्थितियां एकदम बदल जायेगी। तब सरकार की असफलता का स्वभाविक लाभ भाजपा को ही मिलना निश्चित नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह से भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व लगातार सवालों में उलझता जा रहा है उसका असर हर प्रदेश पर पढ़ना तय है। इस परिदृश्य में डॉ. बिन्दल के लिये यह भी बड़ी चुनौती होगा कि वह भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की सरकार के साथ चर्चित सांठ गांठ के आरोपों से कैसे बाहर निकालते हैं। क्योंकि आने वाले समय में सरकार से ज्यादा भाजपा पर सवाल उठने लग पड़ेंगे। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि महत्वपूर्ण सवालों पर भाजपा की चली आ रही चुप्पी के आरोपों को बिन्दल किस तरह से नकार पाते हैं। क्योंकि आने वाले समय में प्रदेश भाजपा में नड्डा, अनुराग ठाकुर और जयराम में ही प्रदेश के मुख्यमंत्री की दौड़ होगी? इनमें कौन नेता अपने-अपने जिलों में कितनी चुनावी जीत हासिल कर पाता है यह बड़ा सवाल होगा और डॉ. बिन्दल के लिये यही बड़ी चुनौती होगी कि वह कैसे इन ध्रुवों को इकठ्ठा चला पाने में सफल होते हैं।

संकट के इस दौर में मानवता की रक्षा की जिम्मेदारी हज़रत मुहम्मद सल्लाहु अलैहि वसल्लम के वैचारिक वंशजों पर

गौतम चौधरी

तेज़ तकनीकी विकास और भौतिक उन्नति के इस युग में, विडंबना यह है कि दुनिया मूल मानव मूल्यों में तीव्र गिरावट का सामना कर रही है। करुणा को स्वार्थ ने ढक दिया है, सच्चाई को गलत जानकारी ने धुंधला कर दिया है और जीवन की पवित्रता को सत्ता की भूख ने कुचल दिया है। नफ़रत के अपराधों, शोषण और युद्धों में वृद्धि से लेकर बढ़ते व्यक्तिवाद और नैतिक उदासीनता तक ऐसा लगता है कि मानवता अपनी नैतिक दिशा भूल गयी है।

इस वैश्विक नैतिक क्षरण की केवल आलोचना करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके लिये एक सामूहिक व तीव्र प्रतिक्रिया की आवश्यकता है, जो ईमानदारी और धर्म सुधारकों, नबियों, महान संदेश वाहकों के द्वारा बताये गये मूल्यों पर अधारित हो। मुसलमानों के लिये यह ज़िम्मेदारी बहुत स्पष्ट है कि वे पैगंबर हज़रत मुहम्मद सल्लाहु अलैहि वसल्लम की शाश्वत शिक्षाओं को पुनर्जीवित करें और अपनाएं, जिनका जीवन शांति, न्याय, दया और मानव गरिमा का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है।

हज़रत मुहम्मद सल्लाहु अलैहि वसल्लम केवल एक धार्मिक नेता नहीं थे अपितु एक सुधारक, शासक, पारिवारिक व्यक्ति और समस्त सृष्टि के लिए रहमत थे। उनके द्वारा नाजिल, इस्लाम के पवित्र ग्रंथ में कहा गया है: 'और हम ने तुम्हें सारे संसारों के लिए केवल रहमत बनाकर भेजा है।' उनका संदेश केव सार्वभौमिक ही नहीं सर्वकालिक और मानवीय चरित्र के उत्थान के लिये है। उन्होंने व्यापार में ईमानदारी, नेतृत्व में करुणा, कठिनाइयों में धैर्य, सत्ता में क्षमा और सभी मुस्लिम या गैर-मुस्लिम, अमीर या गरीब के अधिकारों का सम्मान करना सिखाया है।

आज के समय में मानव मूल्यों में गिरावट अन्याय, भ्रष्टाचार, पारिवारिक विघटन और नैतिक भ्रम के रूप में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। सहानुभूति की जगह उदासीनता ने ले ली है। सत्य को अक्सर स्वार्थ के लिए त्याग दिया जाता है। सोशल मीडिया आत्म-सुधार की जगह आत्म-प्रदर्शन को बढ़ावा देता है। यहां तक कि पवित्र संस्थान भी लालच और पाखंड से दूषित हो चुके हैं। यह केवल सामाजिक नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक संकट है। यदि आस्था और उद्देश्य पर आधारित मजबूत मूल्य न हों, तो मानवता अराजकता में डूब सकती है। दुनिया इस्लाम की ओर देख रही है। इस्लाम के पास एक मजबूत संगठन और व्यवस्थित तंत्र है। इस संगठन और तंत्र का सदुपयोग कर आज की परिस्थितियों से मानवता को निजात दिला सकता है।

इस अंधकार में, पैगंबर मोहम्मद का जीवन और उनकी विरासत उन सभी के लिए प्रकाश स्तंभ है जो रोशनी की तलाश में हैं। मुसलमान केवल इस्लाम के अनुयायी नहीं हैं, वे मोहम्मद के प्रकाश के वाहक भी हैं। अज्ञानता और शत्रुता के बढ़ते दौर में, उनका कर्तव्य है कि वे इस्लाम का प्रतिनिधित्व केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपने चरित्र और आचरण से भी करें।

पैगंबर मोहम्मद ने कहा, 'मुझे केवल अच्छे आचरण को पूर्ण करने के लिए भेजा गया है।' अब यह मिशन उम्मत की जिम्मेदारी है। व्यापार में ईमानदारी, रिश्तों में दया, निर्णयों में न्याय और वाणी में सच्चाई ये सभी दावत (इस्लाम का संदेश देना) के रूप हैं। पैगंबर ने तो यहां तक कहा कि एक मुस्कान भी सदक़ा (दान) है।

मुसलमानों को अपने समुदायों में उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। जातिवाद, अन्याय और असमानता के विरुद्ध खड़े होकर, सद्भाव, सेवा और सभी के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना चाहिए। उन्हें अपने बच्चों को विनम्रता, धैर्य, आभार और सच्चाई जैसे मूल्य केवल किताबों से नहीं, बल्कि अपने दैनिक व्यवहार से सिखाने चाहिए।

पैगंबर (स.अ.) ने लोगों के दिलों को ज़ोर-ज़बरदस्ती से नहीं, बल्कि अपने बेदाग चरित्र से जीता। उनका संदेश दुनिया तक उनकी विश्वसनीयता, करुणा और शांति व न्याय के लिए किए गए अथक प्रयासों से पहुंचा। इस विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए मुसलमानों को कुरआन से जुड़ना होगा, सीरत (पैगंबर का जीवन) का अध्ययन करना होगा, और शिक्षा, मीडिया, राजनीति तथा पारिवारिक जीवन जैसे हर क्षेत्र में नबी की शिक्षाओं को प्रतिबिंबित करना होगा।

मुसलमानों को केवल इबादत में नहीं, बल्कि उद्देश्य में भी एकजुट होना चाहिए। शांति और मानवता के दूत बनने के लिए। ऐसा करके वे अपने रसूल (स.अ.) की शिक्षाओं के सच्चे अनुयायी बनते हैं और दुनिया को वह प्रदान करते हैं जिसकी उसे सख्त ज़रूरत है: सत्य, गरिमा और ईश्वरीय दया की ओर वापसी।

मानव मूल्यों का पतन अपरिहार्य नहीं है। इसे सच्चे विश्वास और कर्म से रोका जा सकता है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद (स.अ.) ने एक ऐसा जीवंत उदाहरण छोड़ा है जो हर युग के लिए मार्गदर्शन करता है। अब यह मुसलमानों का कर्तव्य है कि वे इस संदेश को केवल प्रचार करके नहीं, बल्कि जीकर निभाएं। ऐसा करके वे इस उम्मीद के भूखे संसार के लिए रोशनी की किरण बन सकते हैं।

यह आलेख मुफ्ती अब्दुल्ला कासमी साहब के सहयोग से लिखा गया है। पवित्र ग्रंथ की आयतों का तर्जुमा एवं रसूल के विचार उन्हीं के माध्यम से प्राप्त हुए हैं।

भारत भर में ईएसआई कवरेज का विस्तार करने के लिए एसपीआरईई योजना शुरु

शिमला। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने देश भर में ईएसआई कवरेज का विस्तार करने के उद्देश्य से एसपीआरईई नियोक्ता/कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने की योजना को फिर से शुरू करने को मंजूरी दे दी है। मूल रूप से 2016 में शुरू की गई इस योजना ने 88,000 से अधिक नियोक्ताओं और 1.02 करोड़ कर्मचारियों के पंजीकरण को सफलतापूर्वक सुगम बनाया। नवीनीकृत एसपीआरईई 1 जुलाई से 31 दिसंबर, 2025 तक खुली रहेगी, जो गैर-पंजीकृत नियोक्ताओं और छूटे हुए श्रमिकों-जिनमें संविदा और अस्थायी कर्मचारी शामिल हैं- को ईएसआई अधिनियम के तहत नामांकन करने का एक बार अवसर प्रदान करेगी। योजना के तहत, इस अवधि के दौरान पंजीकरण करने वाले नियोक्ताओं को पंजीकरण की तिथि या उनके द्वारा घोषित तिथि से कवर किया जाएगा, जबकि नए पंजीकृत कर्मचारियों को उनके पंजीकरण की संबंधित तिथियों से कवर किया जाएगा।

दंडित करने के बजाय स्वैच्छिक अनुपालन पर ध्यान केंद्रित करके यह योजना मुकदमेबाजी के बोझ को कम करने, औपचारिक पंजीकरण को प्रोत्साहित करने और हितधारकों के बीच बेहतर सहयोग और सद्भावना को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी।

एमनेस्टी स्कीम 2025

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने एमनेस्टी स्कीम 2025 को मंजूरी दे दी है, जो 1 अक्टूबर, 2025 से 30 सितंबर, 2026 तक की अवधि के लिए कार्यशील विवाद समाधान विंडो है, जिसका उद्देश्य कानूनी झगड़ों को कम करना और ईएसआई अधिनियम के तहत अनुपालन को बढ़ावा देना है। पहली बार, कवरेज के संबंध में नुकसान और ब्याज से जुड़े मामलों के साथ-साथ विवादों को भी शामिल किया गया है। क्षेत्रीय निदेशकों को उन मामलों को वापस लेने का अधिकार दिया गया है, जहां योगदान और ब्याज का भुगतान किया गया है, और पांच वर्ष से अधिक समय पहले बीमित व्यक्तियों के खिलाफ दायर मामलों को भी वापस लेने का अधिकार दिया गया है, जहां कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था।

इस योजना का उद्देश्य न्यायालय के बाहर विवादों के समाधान के लिए एक तंत्र प्रदान करके मुकदमों की संख्या को कम करना है, नियोक्ताओं को व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए आपसी समझौते के लिए आगे आने का अवसर प्रदान करना और सभी हितधारकों की सद्भावना अर्जित करना है।

विद्यमान क्षति संरचना का सरलीकरण

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने ग्रेडेड दरों की पुरानी संरचना को बदलकर स्पष्ट निश्चित दर के पक्ष में अपनी क्षति संरचना को सरल बनाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, पहले के ढांचे में क्षति की अधिकतम दर 25 प्रतिशत प्रति वर्ष थी, जिसे अब कम करके नियोक्ता द्वारा देय राशि पर हर महीने 1 प्रतिशत कर दिया गया है। यह परिवर्तन अनुपालन को बढ़ावा देगा, विवादों को कम करेगा और अधिक अनुकूल विनियामक वातावरण में वृद्धि करेगा।

राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना आरजीएसकेवाई में संशोधन

निगम ने आरजीएसकेवाई के तहत नौकरी छूटने की तिथि से 12 महीने की सीमा से आगे आवेदन जमा करने में छूट देने के लिए ईएसआईसी महानिदेशक को अधिकार सौंपने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

आयुष पर संशोधित ईएसआई नीति – 2023

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने ईएसआईसी की संशोधित आयुष नीति पर विचार किया और उसे मंजूरी दी। यह नीति आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क में एकीकृत करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य समग्र, निवारक और स्वास्थ्य-उन्मुख स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना है। यह कर्मचारी राज्य बीमा निगम लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली समग्र चिकित्सा सेवाओं को बढ़ाने के लिए एक कार्यनीतिक कदम है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पतालों में योग चिकित्सक और पंचकर्म तकनीशियन/परिचारकों की नियुक्ति

निगम ने ईएसआई अस्पतालों में योग चिकित्सक और पंचकर्म तकनीशियन/परिचारकों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।

धर्मार्थ अस्पतालों के साथ अग्रगामी परियोजना

निगम ने निम्न सुविधा प्राप्त क्षेत्रों में धर्मार्थ अस्पतालों के साथ साझेदारी करके ईएसआई लाभार्थियों के लिए स्वास्थ्य सेवा की पहुंच में सुधार करने के लिए एक अग्रगामी परियोजना को मंजूरी दी। ये अस्पताल ओपीडी से लेकर आपातकालीन देखभाल तक व्यापक सेवाएं प्रदान करेंगे, जिससे किफायती, गुणवत्तापूर्ण उपचार सुनिश्चित होगा और साथ ही ईएसआईसी के सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के मिशन को आगे बढ़ाया जा सकेगा। अग्रगामी परियोजना की देश के कुछ जिलों में शुरुआत की जाएगी।

ईएसआई निगम की 196वीं बैठक में सांसद राज्यसभा श्री डोला सेन, सांसद लोकसभा श्री एन.के. प्रेमचंद्र, ईएसआईसी के महानिदेशक श्री अशोक कुमार सिंह, राज्य सरकारों के प्रधान सचिव/सचिव, नियोक्ताओं, कर्मचारियों के प्रतिनिधि और भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और ईएसआईसी के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

हिमाचल में स्वास्थ्य क्षेत्र के आधुनिकीकरण व स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की अनुकरणीय पहल

सरकार द्वारा दो वर्षों में 3.27 करोड़ बाह्य रोगियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान

शिमला। किसी भी समाज, समुदाय, राज्य अथवा राष्ट्र के विकास और तरक्की को इंगित करने के लिए वहां की शिक्षा, स्वास्थ्य प्रणालियों का गहराई से अध्ययन किया जाता है। जो इन क्षेत्रों में अग्रणी होगा, आधुनिक युग की तकनीकों के समावेश के साथ नित नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाएगा, वही प्रगतिशील कहलाएगा और भविष्य की सशक्त तथा सुदृढ़ अर्थव्यवस्थाओं में शुमार होगा। जो राष्ट्र शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के कायाकल्प पर प्रयास केंद्रित करेगा वही इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से अपना नाम दर्ज करेगा। स्वास्थ्य और शिक्षा में किया गया निवेश दशकों एवं पीढ़ियों तक लाभान्वित करता है।

इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश के संसाधनों का सदुपयोग सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया है। हिमाचल प्रदेश को भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो गांवों में बसे लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना असाधारण प्रतिबद्धता एवं समर्पण से ही संभव हो सकता है। व्यवस्था परिवर्तन के अपने अढ़ाई वर्षों के छोटे से कार्यकाल में लीक से हटकर ऐसे हितकारी निर्णय लिए हैं तथा क्रांतिकारी योजनाएं आरम्भ की हैं जिससे कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का सर्वाणीण विस्तार देखने को मिला है। प्रदेश सरकार वर्तमान में राज्य भर में 2,926 राजकीय स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से प्रदेशवासियों को उनके घर-द्वार पर गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं प्रदान कर रही है। इनमें छः चिकित्सा महाविद्यालय, तीन जोनल अस्पताल, 9 क्षेत्रीय अस्पताल, 92 नागरिक अस्पताल, 107 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 585 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा 2,116 उप-स्वास्थ्य केंद्र सहित अन्य संस्थान शामिल हैं।

राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान दुर्गम क्षेत्रों सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों में क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप स्वास्थ्य संस्थानों की क्षमता का विस्तार किया है। नागरिक अस्पताल काजा, जिला लाहौल-स्पीति को 20 बिस्तरों से 50 बिस्तर क्षमता के अस्पताल में स्तरोन्नत किया गया है। जिला हमीरपुर, शिमला व ऊना के नागरिक अस्पतालों सुजानपुर, सुन्नी व हरोली को 50 बिस्तरों से बढ़ाकर 100 बिस्तरों में स्तरोन्नत किया गया है। जिला ऊना के नागरिक अस्पताल इ.एस.आई. गगरेट को नागरिक अस्पताल के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसी प्रकार, जिला सोलन के बद्दी, जिला कांगड़ा के जयसिंहपुर और देहरा में नवीन खण्ड चिकित्सा कार्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है और इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इसके अतिरिक्त सिरमौर जिले के थोड़ा जाखल, उठारी, नया पजौर में तीन नए स्वास्थ्य उप-केंद्र और कोटापब व हलाह में दो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। सिरमौर की ही बशील ग्राम पंचायत ममलीग में भी एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला गया है। जिला सोलन के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिग्गल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है।

स्वास्थ्य संस्थानों के स्तरोन्नयन एवं विस्तार तथा प्रदेश के सभी संस्थानों में सुनिश्चित की जा रही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के फलस्वरूप वर्तमान प्रदेश सरकर के कार्याकाल के दौरान जनवरी, 2023 से दिसम्बर, 2024 तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगभग 3 करोड़ 27 लाख बाहय रोगियों और लगभग 37 लाख 50 हजार अंतरंग रोगियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा चुकी हैं।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश भर में उच्च गुणवत्ता मानकों की स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक 68 विधानसभा क्षेत्र में एक-एक तथा लाहौल-स्पीति में दो आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोलने का महत्त्वाकांक्षी निर्णय लिया है।

अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में यह स्वास्थ्य संस्थान खोले जा चुके हैं तथा शेष स्थानों में खोलने की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है। प्रत्येक 69 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान में 134 प्रकार की प्रयोगशाला से संबंधित सुविधाएं तथा मेडिसिन, सर्जरी, स्त्री रोग, बाल रोग एनेस्थिसियोलॉजी और रेडियोलॉजी के विशेषज्ञ होंगे। इसके अलावा पर्याप्त चिकित्सा स्टाफ, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्स-रे सहित आधुनिक उपकरण एवं सुविधाएं उपलब्ध होंगी। चिन्हित आदर्श संस्थानों में चरणबद्ध तरीक से आधुनिकतम एम.आर.आई एवं सी.टी. स्कैन की सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य भी प्रगति पर है। आदर्श संस्थानों में मशीनरी व उपकरण खरीद के लिए बजट का प्रावधान किया है तथा खरीद प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

राज्य सरकार द्वारा अढ़ाई वर्षों के कार्यकाल में 30 मार्च, 2025 तक 185 चिकित्सा अधिकारी, 130 स्टाफ नर्स, छः लैब असिस्टेंट, 67 मेडिकल लैबोरेट्री तकनीशियन, 45 फार्मासिस्ट ऑफिसर, 61 ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट और सात फीजियोथेरेपिस्ट सहित विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्तियां प्रदान की गई हैं।

राज्य सरकार ने स्वास्थ्य संस्थानों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 221 चिकित्सा अधिकारियों, 23 वार्ड सिस्टर, छः रेडियोग्राफर, 14 मैडिकल लैब तकनीशियन ग्रेड-2, 213 ओटीए, 11 फार्मासिस्ट, तीन खंड चिकित्सा अधिकारी और चार फिजियोथेरेपिस्ट सहित कुल 491 विभिन्न श्रेणियों के पद सृजित किए हैं।

प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सभी चिकित्सा महाविद्यालयों, 69 नागरिक अस्पतालों, क्षेत्रीय अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आधुनिक मशीनें खरीदने के लिए 1,730 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। वर्तमान में 20 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में डायलिसिस सेवाएं प्रदान की जा रही हैं जबकि 49 संस्थानों में 41.62 करोड़ रुपये से डायलिसिस सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसी प्रकार 11 संस्थानों में ब्लड स्टोरेज यूनिट्स की स्थापना की जाएगी। आईजीएमसी शिमला, एआईएमएसएस चमियाना शिमला, हमीरपुर व नेरचौक चिकित्सा महाविद्यालयों में आधुनिक एमआरआई तथा आईजीएमसी में पैट स्कैन की सुविधा प्रदान की जाएगी।

प्रदेश सरकार द्वारा 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के वृद्धजनों के लिए घर-घर जाकर स्वास्थ्य जांच सुविधाएं प्रदान करने के लिए 'मुख्यमंत्री वृद्धजन देखभाल योजना' पर कार्य किया जा रहा है।

प्रदेश सरकार के इन प्रयासों के फलस्वरूप राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र का कायाकल्प और आधुनिकीकरण हो रहा है और निकट भविष्य में हिमाचल प्रदेश उत्कृष्ट स्वास्थ्य संस्थानों और विश्व स्तरीय सेवाओं व सुविधाओं के प्रदाता के रूप में ख्याति अर्जित करेगा। देश व दुनिया स्वास्थ्य क्षेत्र में हिमाचल की विकास यात्रा का अनुसरण करेगी साथ ही, हिमाचल हेल्थ पर्यटन का एक आकर्षक गंतव्य बनकर उभरेगा।

मल्टी टास्क वर्कर्स का मासिक मानदेय 5000 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये करने की मंज़ूरी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गये। राज्य कैबिनेट ने लेवल-11 वेतनमान के पदों को ग्रुप-बी से ग्रुप-सी में पुनर्वर्गीकृत करने को

स्वीकृति प्रदान की। इस निर्णय के तहत अब केवल बोनाफाइड (स्थाई/मूल) हिमाचली ही ग्रुप-सी पदों के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। पहले ग्रुप-बी श्रेणी के तहत आने वाले इन पदों की भर्ती हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती थी, और देशभर के अभ्यर्थी इन पदों के लिये आवेदन कर सकते थे। अब इनकी भर्ती प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से ग्रुप-सी के नियमों के तहत की जाएगी।

राज्य कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग के लगभग 5000 मल्टी टास्क वर्कर्स (बहुकार्य कर्मचारी) का मासिक मानदेय 5000 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये करने को मंज़ूरी दी।

राज्य कैबिनेट ने ग़ैर-सरकारी दुग्ध सहकारी समितियों को दूध आपूर्ति करने वाले किसानों के लिए दूध प्रोत्साहन योजना आरम्भ करने का निर्णय लिया। इसके तहत दुग्ध उत्पादकों को 3 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी (उपदान) डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर/प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से दी जाएगी।

कैबिनेट बैठक में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) का मुख्यालय शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने को स्वीकृति प्रदान की गई। यह निर्णय कांगड़ा को हिमाचल प्रदेश की पर्यटन राजधानी घोषित किए जाने के मद्देनज़र लिया गया है। इस निर्णय से शिमला शहर पर भीड़ का दबाव कम करने में सहायता मिलेगी।

बैठक में ज़िला पुलिस, देहरा की पुलिस लाइनों में विभिन्न श्रेणियों के 101 पदों के सृजन तथा उन्हें भरने की मंज़ूरी दी गई।

राज्य सरकार ने स्वरोज़गार को प्रोत्साहित करने और पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु ब्याज़ सब्सिडी प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय के तहत जनजातीय क्षेत्रों में 100 किलोवॉट से 1 मैगावॉट की परियोजनाओं पर 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी जबकि गैर-जनजातीय क्षेत्रों में 250 किलोवॉट से 2 मैगावॉट की परियोजनाओं पर 4 प्रतिशत ब्याज़ सब्सिडी मुहैया करवाई जाएगी।

राज्य कैबिनेट ने हिमऊर्जा और चयनित ग्राम पंचायतों के बीच 100 पंचायतों में 500 किलोवॉट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को स्वीकृति प्रदान की। प्रत्येक परियोजना से लगभग 25 लाख रुपये मासिक आय होने की उम्मीद है। इस आय का 30 प्रतिशत हिस्सा हिमऊर्जा को, 20 प्रतिशत राज्य सरकार को और 40 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायतों को मिलेगा। अतिरिक्त 10 प्रतिशत आय अनाथों तथा विधवाओं के कल्याण हेतु पंचायतों को प्रदान की जाएगी।

कैबिनेट ने प्रदेश की 3645 पंचायतों में पंचायत आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र स्थापित करने का फ़ैसला लिया है, ताकि प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में मानवीय जीवन और संपत्तियों की रक्षा के लिए त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके।

मुख्यमंत्री ने शिमला में 12वीं हिमाचल प्रदेश पुलिस हाफ मैराथन विजेताओं को किया सम्मानित

शिमला/शैल। नशे के विरूद्ध जागरूकता बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा शिमला में 12वीं हिमाचल प्रदेश पुलिस हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मैराथन

विजेताओं को सम्मानित किया। इस मैराथन में पुरूष, महिला और वरिष्ठ नागरिक 75 वर्ष से अधिक श्रेणी के प्रतिभागियों ने भाग लिया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नशे संबंधी गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों की संलिप्ता पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने नशे संबंधी गतिविधियों में शामिल 80 सरकारी कर्मचारियों के विरूद्ध सख्त कारवाई अमल में लाई है। नशे की तस्करी संबंधी मामलों में पुलिस कर्मियों की संलिप्तता भी सामने आई है और राज्य सरकार पुलिस बल में अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पुलिस मैनुअल में संशोधन पर विचार कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार निकट भविष्य में बड़े स्तर पर नशा विरोधी अभियान शुरू करने की तैयारी कर रही है। नशे पर अंकुश लगाने के लिए पंचायत स्तर पर मैपिंग करवाई जा रही है। सरकार नशे की तस्करी पर रोक लगाने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का भी गठन कर रही है जिसके लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग को मजबूत करने के लिए 500 नए पद भरे जाएंगे।

नशे के प्रति राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने पीआइटी-एनडीपीएस अधिनियम को लागू किया है। इस अधिनियम के तहत 40 डिटेंशन आदेशों को मंज़ूरी दी गई जिनमें से इस वर्ष 36 आदेश जारी किए गए। सरकार ने नशे के तस्करों के विरूद्ध कड़ा रूख अपनाते हुए सात नशा तस्करों की संपत्तियों को गिराया गया है और अन्य के खिलाफ सक्रियता से कारवाई सुनिश्चित की जा रही है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हाफ मैराथन 21.5 किलोमीटर पुरूष वर्ग के विजेता रविदास और महिला वर्ग की विजेता रूबी कश्यप को 51-51 हजार रुपये के पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त मिनी मैराथन 10 किलोमीटर पुरूष वर्ग के विजेता रवि चौधरी, महिला वर्ग में सुनीता, ड्रीम रन 3 किलोमीटर 16 से 30 आयुवर्ग पुरूष वर्ग के प्रथम विजेता मोहम्मद सोहेल, महिला वर्ग के लिए विपाशा वर्मा, 31 से 45 आयुवर्ग पुरूष वर्ग के प्रथम विजेता नागेंद्र पाल, महिला वर्ग के लिए प्रतिभा, 46 से 60 आयुवर्ग पुरूष वर्ग के प्रथम विजेता कुलदीप, महिला वर्ग में विजेता, 10 से 15 आयुवर्ग के लिए पुरूष वर्ग में हर्ष कुमार, महिला वर्ग रीतिका वर्मा को सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री ने 'हार्मनी ऑफ पाइन' के नशे पर जन जागरूकता आधारित एक विशेष गीत को भी जारी किया।

मुख्यमंत्री ने एचआइवी, एसटीआई, टीबी और हेपेटाइटिस संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 12 ई-स्कूटरों को झंडी दिखाकर रवाना किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने ओक ओवर शिमला से 12 ई-स्कूटरों को झंडी दिखाकर रवाना किया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा स्वास्थ्य विभाग को प्रदान किए गए इन

ई-स्कूटरों को प्रदेश के आठ जिलों में तैनात किया जाएगा। सरकार की इस पहल का उद्देश्य घर-द्वार के निकट एचआइवी, एसटीआई, टीबी और हेपेटाइटिस से ग्रसित मरीजों को दवाईयां, जांच और परामर्श की बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाना है।

प्रदेश में कोई भी व्यक्ति बेहतर उपचार सुविधा से वंचित न रहे इसके दृष्टिगत हिमाचल में पहली बार इस तरह का समर्पित प्रयास किया गया है। सरकार के इस संवेदनशील निर्णय से इन बीमारी से ग्रसित मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी और उन्हें दवाई की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी जिससे वे स्वस्थ्य जीवन व्यतीत कर सकेंगे।

स्वास्थ्य विभाग और राज्य एड्स नियंत्रण समिति की इस पहल की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रेड रिबन क्लब, युवा, शैक्षणिक संस्थान और गैर सरकारी संस्थाएं एचआइवी के बारे में लोगों को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रदेश को एचआइवी मुक्त बनाना सरकार और लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह ई-स्कूटर सरकार के प्रयासों को और अधिक सुदृढ़ करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 6 हजार से अधिक व्यक्ति एचआइवी से ग्रसित हैं, जिनमें से अधिकांश में इस वायरस का प्रभाव कम है जो सरकार की नीतियों और निरंतर प्रयासों की सफलता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत प्रदेश सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है और इसी दिशा में स्वास्थ्य विभाग को ई-स्कूटर प्रदान किए गए हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल ने कहा कि राज्य एड्स नियंत्रण समिति राज्यभर के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्थापित 471 रेड रिबन क्लबों के माध्यम से सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। इसके साथ ही स्कूलों में किशोर शिक्षा कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूल से बाहर के युवाओं में एचआईवी के प्रति जागरूकता लाने के लिए युवा सेवाएं एवं खेल विभाग और नेहरू युवा केंद्र संगठन भी मिलकर कार्य कर रहे हैं।

केन्द्र ने प्रदेश की सड़कों के लिए 3667 करोड़ रूपये की वार्षिक योजना को दी स्वीकृति:विक्रमादित्य सिंह

शिमला/शैल। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि केन्द्र सरकार ने प्रदेश में सड़कों, पुलों इत्यादि के निर्माण कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के 3667 करोड़ रूपये के प्रदेश सरकार की वार्षिक योजना को स्वीकृति प्रदान की है। इनमें प्रदेश के सभी जिलों में राष्ट्रीय उच्च मार्गों में पुलों के निर्माण, सड़कों के स्तरोन्नयन और क्रैश बैरियर निर्माण इत्यादि के कार्य शामिल हैं।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कुछ दिन पूर्व उन्होंने केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर प्रदेश के महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में राष्ट्रीय उच्च मार्ग के अधीन 1200 किलोमीटर सड़कें हैं जिनके रख-रखाव एवं सुधार कार्यों के लिए केंद्र सरकार से महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्रदेश सरकार ने 2600 करोड़ रूपये की वार्षिक योजना स्वीकृति के लिए भेजी थी लेकिन प्रदेश को मात्र 269 करोड़ रूपये ही प्राप्त हुए थे जो काफी कम थे। प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 3667 करोड़ रूपये का वार्षिक योजना भेजी थी, जिसे जून माह में केंद्र सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है।

लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि इस दौरान उन्होंने कुल्लू जिला के राष्ट्रीय उच्च मार्ग 305 में जलोड़ी जोत के नीचे सुरंग निर्माण का मामला भी उठाया जिसे केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर 1452 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं। उन्होंने कहा कि इस सुरंग निर्माण से जहां इस क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बल मिलेगा, वहीं इसका लाभ इस क्षेत्र के लाखों लोगों को प्राप्त होगा।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या पांच में ब्रौनी नाला में लगातार हो रहे भू-स्खलन के कारण सड़क को नुकसान हो रहा है। इस स्थान पर पुल निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 135 करोड़ रूपये स्वीकृत किये हैं। इसके अतिरिक्त काला आंब-पांवटा साहिब-देहरादून सड़क के 4 लेन निर्माण कार्य जिसमें भू-अधिग्रहण, निर्माण पूर्व गतिविधियां शामिल हैं के लिए भी केंद्र सरकार ने 1385 करोड़ रूपये स्वीकृत किये हैं।

विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश के लिए धनराशि स्वीकृत करने के लिए केन्द्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी एवं केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि प्रदेश व केंद्र सरकार के बीच समन्वय की स्थिति भविष्य में भी बनी रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार केंद्र के सहयोग से राज्य के प्रत्येक क्षेत्र का समग्र व संतुलित विकास सुनिश्चित बनाने की दिशा में निरन्तर कार्यरत है।

लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि उन्होंने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर मंडी व कुल्लू जिला को जोडने वाली भुभू जोत सुरंग एवं सड़क निर्माण का मामला भी उठाया। इस दौरान उन्होंने रक्षा मंत्री से भुभू जोत सुरंग निर्माण के लिए सड़क को रक्षा रणनीतिक मार्ग घोषित करने का भी आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण सड़क निर्माण पर भी आने वाले समय में प्रदेश को सकारात्मक परिणाम मिलने की आशा है। इस महत्वपूर्ण सड़क निर्माण के कारण पठानकोट व कुल्लू के मध्य लगभग 40 से 50 किलोमीटर की दूरी कम होगी तथा इसका लाभ पर्यटकों, प्रदेश के लोगों सहित भारतीय सेना को भी होगा।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने तपोवन में सीपीए ज़ोन – 2 वार्षिक सम्मेलन का शुभारम्भ किया

शिमला/शैल। कॉमनवेल्थ पारलियामेंटरी एसोसिएशन के भारत क्षेत्र ज़ोन-2 का दो दिवसीय वार्षिक सम्मेलन धर्मशाला के तपोवन स्थित विधानसभा परिसर में शुरू हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने इस सम्मेलन का शुभारम्भ किया।

इस सम्मेलन में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू-काश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य सचेतक और उप-मुख्य सचेतक शामिल हुए। इसके अलावा कर्नाटक, असाम, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष विशेष रूप से उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए कहा कि यह सम्मेलन लोकतन्त्र को मजबूत करने, विधायी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाने और आपसी सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को इस सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए बधाई दीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश ने पहली बार लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास किया गया लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने कानून के अनुसार कारवाई कर जिम्मेदार विधायकों को अयोग्य घोषित किया। उन्होंने कहा कि लोकतन्त्र की रक्षा के लिए 'एंटी डिफेक्शन लॉ' लागू करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश विधानसभा ने आयोग्य विधायकों की पेंशन पर रोक के लिए बिल पास किया है, जिसे राज्यपाल को स्वीकृति के लिए भेजा गया है।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश डिजिटल लोकतन्त्र में देश में अन्य राज्यों के लिए अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। वर्ष 2014 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा देश की पहली कागज रहित विधानसभा बनी। प्रदेश विधानसभा में सभी कार्य डिजिटल माध्यम से सुनिश्चित किए जा रहे हैं। उन्होंने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' नीति के तहत वर्ष में एक बार उप-चुनाव करवाने का सुझाव भी रखा और लोकसभा अध्यक्ष से इसे राष्ट्रीय मंच पर उठाने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने राज्य की कठिन पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए अलग नीति की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के उपरांत राज्य को राजस्व का नुकसान हुआ है। इसलिए केन्द्र को चाहिए कि वह पहाड़ी राज्यों के लिए अलग नीति तैयार करे।

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सभी का सम्मेलन में उपस्थित होने पर आभार व्यक्त किया।

संसदीय मामले मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने भी एंटी डिफेक्शन लॉ पर बल दिया। उन्होंने कहा कि यह बिल लोकतंत्र की मजबूती के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए विधानसभा अध्यक्ष को बधाई दी।

राज्यसभा के उपाध्यक्ष डॉ. हरिवंश नारायण सिंह ने भी अपने बहुमूल्य विचार प्रस्तुत किए।

आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष विनय कुमार और विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि भी सम्मेलन में उपस्थित थे।

हिमाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस का भव्य आयोजन

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस राज्यभर में विविध कार्यक्रमों के साथ उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित एक प्रमुख कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आर.डी. नज़ीम, आईएएस, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग उपस्थित

रहे। उन्होंने राज्य के उद्यमियों, नीति-निर्माताओं तथा एमएसएमई क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के आर्थिक विकास में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

उन्होंने जानकारी दी कि राज्य में अब तक 2 लाख से अधिक एमएसएमई उद्यम उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत हैं, जो लगभग 7.8 लाख लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने एमएसएमई इकाइयों और उनसे जुड़े हितधारकों के योगदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में उन्हें सशक्त करने हेतु सामूहिक प्रयासों की अपील की।

उद्योग निदेशालय में आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में निदेशक उद्योग, डॉ. यूनुस, आईएएस ने बैंक प्रतिनिधियों, विभागीय अधिकारियों और एमएसएमई प्रतिनिधियों को संबोधित किया। उन्होंने राज्यभर में एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने हेतु जारी रणनीतिक पहलों की जानकारी दी। उन्होंने नवाचार को प्रोत्साहन, वित्त, बाज़ार और संस्थागत सहायता तक पहुंच की मजबूती जैसे उपायों पर बल दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर विभागीय अधिकारी राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं को एमएसएमई तक पहुंचाने और उनके प्रभावी क्रियान्वयन में जुटे हुए हैं, जिससे समावेशी औद्योगिक विकास और सतत प्रगति सुनिश्चित हो सके।

राज्य के विभिन्न जिलों में जिला उद्योग केंद्रों और सिंगल विंडो क्लीयरेंस अथॉरिटीज़ द्वारा भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर एमएसएमई की भूमिका को रेखांकित किया गया और राज्य तथा केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए गए।

हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक प्रगति:

राज्य ने कृषि-प्रधान अर्थव्यवस्था से निकल कर विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में संतुलित विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। HP आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, द्वितीयक क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में योगदान 1950-51 में 7.41% से बढ़कर 1990-91 में 26.50% तथा 2023-24 में 39.98% हो गया है।

राज्य से निर्यात 2003-04 में 550 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 19,185 करोड़ तक पहुंच गया है।

हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति 2019 के तहत एमएसएमई इकाइयों को टैक्स में छूट, ब्याज अनुदान, औद्योगिक भूखंड के लिए ब्याज-मुक्त 8 समान वार्षिक किश्तों जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' में राज्य की रैंकिंग 17वें स्थान से सुधार कर 7वें स्थान पर पहुंची है। यह 180 से अधिक ऑनलाइन सेवाओं और सेल्फ-सर्टिफिकेशन की सुविधा के चलते संभव हुआ है।

राज्य में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र तेज़ी से विकसित हो रहा है। अब तक 407 स्टार्टअप इनक्यूबेट हो चुके हैं, जिनमें से 107 का व्यवसायीकरण किया जा चुका है। आईआईटी मंडी और आईआईएम सिरमौर जैसे संस्थानों में 14 इनक्यूबेशन सेंटर कार्यरत हैं।

RAMP कार्यक्रम के तहत 109 करोड़ की राशि डिजिटल परिवर्तन, सतत विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में प्री-इनक्यूबेशन, और TReDS जैसी योजनाओं के माध्यम से एमएसएमई प्रदर्शन को बेहतर बनाने हेतु आवंटित की गई है।

औद्योगिक अवसंरचना को बढ़ावा देने हेतु बद्दी और ऊना में फार्मा लैब, एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, गैस पाइपलाइन कनेक्टिविटी, कौशल विकास केंद्र तथा पुरुष एवं महिला हेतु वर्किंग हॉस्टल जैसी सुविधाएं सुलभ कराई जा रही हैं।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जनजातीय जिलों को दी करोड़ों रुपये की सौगात

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के पांच दिवसीय दौरे पर आये केंद्रीय संसदीय कार्य एवं जनजातीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने काजा में प्रधानमन्त्री जन विकास योजना के तहत कई कल्याणकारी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उनमें प्रमुख उच्च ऊंचाई खेल प्रशिक्षण केंद्र, आइस हॉकी रिंग और अत्याधुनिक खेल प्रशिक्षण केंद्र है। यह योजना केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से संभव हो रही है, जो लाहुल-स्पीति जैसे दुर्गम क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। उन्होंने कहा कि पुरे देश में लाहौल-स्पीति जिला को अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय द्वारा सबसे अधिक धनराशी दी गयी है।

काज़ा में केंद्रीय मंत्री ने उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिये प्रधानमंत्री मोदी एवं केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

केंद्रीय मंत्री ने ताबा से आगे सड़क की खस्ता हालत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस सड़क की टेंडरिंग प्रक्रिया पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ वर्षों में शिमला से रामपुर होते हुए किन्नौर-लाहौल स्पिति पूरे की सड़कें डबल लेन की जायेंगी। सड़क मार्ग चौड़े होने से लोगों की जीवन शैली में भी तेजी से बदलाव देखने को मिलेगा। किरेन रिजिजू ने स्पिति के होम स्टे कॉसेप्ट की भी जमकर सराहना की।

जनजातीय जिलों के दौरे के अंतिम चरण में केलांग में वाहन प्रधानमंत्री जनकल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत केलांग मल निकासी योजना का शिलान्यास किया। इस परियोजना के तहत केलांग में आधुनिक मल निकासी प्रणाली विकसित की जाएगी, जिससे केलांग और बिलिंग गांव के लोग लाभान्वित होंगे। उन्होने कहा कि जनजातीय जिलों का दौरा विशेष रहा जिसमे स्थानीय लोगों से मिलने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि इस दौरान कई प्रमुख गोम्पा और बौध मठों के लोग अपनी समस्यों को लेकर उनसे मिले हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे प्राचीन मठों और प्रमुख गोम्पाओं के जीर्णोद्वार के लिए बुद्धिस्ट डेवलपमेंट प्लान बनाकर सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि गोम्पा और बौध मठों द्वारा जो भी आवेदन आयेंगे, उन्हें धनराशी उपलब्ध करवा दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि अटल टनल के निर्माण से इस क्षेत्र के लोगों कि समस्याएं पहले से कम हुई हैं। उन्होंने कहा कि विकास कि दृष्टी से लाहुल-स्पीती को आगे ले जाना दोनों सरकारों कि सामूहिक जिम्मेवारी है। उन्होंने कहा कि एक्स्ट्रीम बॉर्डर एरिया क्षेत्र के लोगों तक मुलभुत सुविधायें पहुंचाने के लिए गृह मंत्रालय ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम चलाया है। इस योजना में ऐसे गांव में सडक, स्कूल, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करवाई जायेंगी।

पेंशनभोगी 1 जुलाई से 30 सितम्बर2025 तक जीवन प्रमाण-पत्र जमा करवाएं

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश कोष नियमावली एवं वित्त विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के तहत राज्य के सभी पेंशनभोगियों को वर्ष 2025-26 के लिए अपना जीवन प्रमाण-पत्र आवश्यक दस्तावेजों सहित 1 जुलाई 2025 से 30 सितम्बर, 2025 के मध्य अनिवार्य रूप से जमा करवाने के लिए कहा गया है। सुनिश्चित करें। जीवन प्रमाण पत्र विभाग की वेबसाइट http://Himkosh.hp.nic.in. से डाउनलोड किया जा सकता है, जिसे भरकर संबंधित पटवारी, पंचायत सचिव, बैंक मैनेजर तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के किसी भी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करवा कर किसी भी कोषगार कार्यालय में जमा करवाया जा सकता है।

विभाग क प्रवक्ता ने बताया कि इसके अतिरिक्त, पेंशनभोगी राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) कोषगार या सामान्य सेवा केंद्र सीएससी में उपलब्ध बायोमैट्रिक उपकरण के माध्यम से जीवन प्रमाण पोर्टल www.jeevan pramaan.gov.in. पर बायोमिट्रिक सत्यापन करवा कर भी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आधार संख्या पर आधारित डिजिटल प्रमाण पत्र कोष कार्यालय द्वारा एक वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

प्रवक्ता ने बताया कि जिन पेंशनभोगियों ने पहले ही कोषागार में अपनी आधार संख्या पंजीकृत करवा रखी है, वह किसी भी स्थान से बायोमिट्रिक यंत्र के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं, और उन्हें अलग से कोषगार में दस्तावेज जमा करवाने की आवश्यकता नहीं होगी।

उन्होंने बताया कि पेंशनभोगी यदि ऑनलाइन डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र के माध्यम से बायोमिट्रिक सत्यापन करवाते हैं, तो उन्हें भविष्य में कोषगार कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। जीवन प्रमाण पोर्टल पर किया गया बायोमिट्रिक सत्यापन एक वर्ष तक वैध रहेगा।

विभागीय प्रवक्ता ने सभी पेंशनभोगियों से आग्रह किया है कि वह समय सीमा के भीतर अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना सुनिश्चित करें ताकि पेंशन वितरण प्रक्रिया को निर्बाध बनाए रखा जा सके।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

यदि कांग्रेस हाईकमान ने समय रहते ध्यान न दिया तो प्रदेश हाथ से निकल जायेगा

शिमला/शैल। प्रदेश के छः बार मुख्यमंत्री रहे स्व. राजा वीरभद्र सिंह के चर्तुवार्षिक पर पदम पैलस रामपुर में हुये आयोजन में जिस संख्या में उनके समर्थक एवं शुभचिंतक हाजिर हुये हैं उससे यह प्रमाणित हो गया है कि प्रदेश की राजनीति में वह अभी भी एक प्रभावी फैक्टर बने हुये हैं। स्व. वीरभद्र सिंह की मृत्यु के बाद बनी पहली कांग्रेस सरकार में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गयी हैं कि जनता कांग्रेस की सरकार के नाम पर इसकी तुलना वीरभद्र सिंह सरकार से करने पर विवश हो गये हैं। यह माना जा रहा है कि यदि शिमला में उनकी प्रतिमा के अनावरण का कार्यक्रम भी संपन्न हो पाता तो शायद रामपुर में इससे दो गुना लोग इकठे हो जाते। इस अवसर पर आये आम आदमी का ही यह असर रहा है कि मुख्यमंत्री को यह कहना पड़ा है कि यदि प्रतिभा सिंह ही प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष बनी रहती हैं तो इसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अभी शिमला में उनकी प्रतिमा का अनावरण होना है। प्रतिमा रिज पर स्थापित हो चुकी है। रिज पर प्रतिमा की स्थापना को लेकर एक सुमन कदम पहले ही नगर निगम को एक पत्र लिखकर आपत्ति उठा चुकी है। अब रामपुर के आयोजन के बाद कुछ हल्कों में यह सवाल भी उठाया जाने लगा है कि यदि स्व. वीरभद्र सिंह की प्रतिमा रिज पर स्थापित हो सकती है तो स्व. राजीव गांधी की प्रतिमा को रिज पर स्थान क्यों नहीं। राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री रहे हैं और देश के लिए बलिदान हुये हैं उनका देश के लिये योगदान रहा है। यह सवाल उठाया जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस विषय पर खामोश क्यों हैं। यह सवाल तब उठा है जब यह सामने आया की स्व. वीरभद्र सिंह के प्रतिमा को रिज पर स्थान प्रियंका गांधी के हस्ताक्षेप के बाद की संभव हो पाया है। यह सवाल आने वाले दिनों में कितना बड़ा राजनीतिक आकार ले पाता है यह देखना दिलचस्प होगा।

लेकिन स्व. राजीव गांधी की प्रतिमा का सवाल जिस तरह से उठा है उससे कांग्रेस की पुरानी राजनीति अनायास ही फिर चर्चा में आ जाती है। क्योंकि जब स्व. वीरभद्र सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उस समय दोनों के राजनीतिक रिश्ते किस तरह के थे इससे पूरा प्रदेश परिचित है। बल्कि उसी दौरान वीरभद्र ब्रिगेड बनाने की चर्चाएं चली थी। वीरभद्र ब्रिगेड के जो प्रदेश अध्यक्ष बनाये गये थे उनके साथ सुक्खू के रिश्ते कोई सौहार्दपूर्ण नहीं रहे हैं। यह सही है कि इस ब्रिगेड को उसी दौरान भंग भी कर दिया गया था। इस ब्रिगेड के बहुत से पदाधिकारी आज सुक्खू के निकटस्थों में गिने जाते हैं। ऐसे में स्व. राजीव गांधी की प्रतिमा का सवाल जिस ढंग से उठाकर उसमें राहुल और प्रियंका का जिक्र लाया गया है उसके राजनीतिक मायने बहुत दूरगामी होंगे। प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणीयां राज्य स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक पिछले नवम्बर से भंग है। इसी बीच नया अध्यक्ष बनाये जाने की चर्चा उठी। इस चर्चा में यहां तक बातें उठी कि दलित वर्ग से नया अध्यक्ष होगा। विधायक विनोद सुल्तानपुरी को लेकर यह कहा जाने लगा कि उनका बनना तय हो गया है। फिर विनय कुमार की चर्चा चली कि वह अध्यक्ष हो रहे है। इसी बीच कृषि मंत्री चंद्र कुमार के त्यागपत्र की चर्चा उठी। अब स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने जब एक जनसभा में यह कहा कि अगला चुनाव वह नहीं बल्कि उनका बेटा लड़ेगा तब यह चर्चा जुड़ गयी की शांडिल त्यागपत्र देकर प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे और उनकी जगह अवस्थी मंत्री बनेंगे। लेकिन यह चर्चा भी आगे आकार लेती नजर नहीं आ रही है।

इस समय प्रदेश सरकार जिस तरह के वित्तीय संकट से गुजर रही है उसमें लोगों पर करोड़ों का बोझ लगाने के अतिरिक्त सरकार और कुछ नहीं कर पा रही है। यदि केंद्र सरकार द्वारा पोषित और बाहय सहायता प्राप्त योजनाओं का स्त्रोत किसी कारण से बन्द हो जाये तो शायद सरकार चार दिन भी न चल पाये यह स्थिति है। वित्तीय संकट का प्रभाव विधानसभा चुनावों में दी गई गारंटीयों को पूरा करने पर पड़ रहा है। इसी कारण से सरकार नियमित रोजगार के स्थान पर 6600 और 5500 रुपए प्रतिमाह का रोजगार ही दस हजार पैरापम्प ऑपरेटर और मल्टीपर्पज वर्करज को दे पायी है। ऊपर से विमल नेगी की मौत प्रकरण और बाढ़ में बहकर आयी करोड़ों की लकड़ी के स्त्रोत के सवालों ने सरकार को और असहज कर रखा है। इस स्थिति का असर अब विधायकों और दूसरे कार्यकर्ताओं पर भी पढ़ने लगा है वह भी मुखर होने लगे हैं। विधायक कुलदीप राठौर और वन निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची का अपरोक्ष संवाद इसका उदाहरण है। यदि समय रहते हाईकमान ने प्रदेश की ओर ध्यान न दिया तो स्थितियां नियंत्रण से बाहर हो जायेगी।

मानसून के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रबंधन को लेकर एनएचएआई सक्रिय

शिमला/शैल। मानसून के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर जलभराव की समस्या से निपटने के लिए एनएचएआई देश भर में बाढ़ से जुड़ी तैयारियों को लेकर सक्रिय कदम उठा रहा है।

मानसून के मौसम के दौरान प्रभावी समाधान प्रदान करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाते हुए एनएचएआई ने 15 दिवसीय अभियान शुरू किया है, जिसमें एनएचएआई के अधिकारी, ठेकेदार और सलाहकार विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की जा सके, जो क्षतिग्रस्त होने की संभावना वाले हैं या जलभराव या भूस्खलन से प्रभावित होने की संभावना है, ताकि राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों और पुलियों जैसी संरचनाओं के माध्यम से जल मार्ग का मुक्त प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके।

इसके अलावा वर्षा जल संचयन संरचनाओं की सफाई और गाद निकालने का काम भी किया जा रहा है। इसके अलावा पानी का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए नालियों और आउटलेट को ठीक किया जा रहा है। बाढ़ और जलभराव वाले क्षेत्रों में डायवर्जन/स्लिप सड़कों और मुख्य मार्गों पर गड्डों की मरम्मत, पुलियों और क्रॉस नालियों की सफाई और आर.ई. वॉल वेप होल और जल निकासी की सफाई के प्रयास किए जा रहे हैं। मानसून की बारिश के दौरान कनेक्टिविटी को सक्षम करने और यातायात की सुरक्षित और सुचारू आवाजाही प्रदान करने के लिये विभिन्न जलभराव वाले स्थलों पर उत्खनन मशीनें, रेत की बोरियां, साइनेज जैसे आपातकालीन उपकरण और सामग्री जुटाई जा रही है।

इसके अलावा एनएचएआई बाढ़/भूस्खलन की पूर्व चेतावनी पर कारवाई करने और संवेदनशील स्थानों पर मशीनरी और जनशक्ति को शीघ्रता से पहुंचाने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों, स्थानीय अधिकारियों और प्रशासन के साथ निकट समन्वय में काम कर रहा है। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजमार्गों पर बाढ़/जलभराव की स्थिति में तेजी से राहत प्रदान करने के लिए विभिन्न स्थलों पर आवश्यक उपकरणों और मशीनरी के साथ 24X7 आपातकालीन प्रतिक्रिया दल तैनात किए जाएंगे। संवेदनशील स्थलों की सूक्ष्म निगरानी के लिए एनएचएआई के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में त्वरित प्रतिक्रिया टीमें गठित की गई हैं।

तकनीक-संचालित निगरानी और अलर्ट का उपयोग करते हुए, एनएचएआई एआई-आधारित इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का लाभ उठाकर और एनएचएआई राजमार्गयात्रा ऐप और आईएमडी की मेघदूत ऐप पर मोबाइल अलर्ट के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रियों को वास्तविक समय के मौसम और यातायात अपडेट प्रदान करेगा। ड्रोन का उपयोग समस्याओं का पता लगाने, सड़कों की ढलान को उचित बनाए रखने तथा फुटपाथ पर आई दरारों की पहचान करने और उन्हें ठीक करने के लिए किया जा रहा है।

भारत में मानसून की शुरुआत के साथ ही एनएचएआई ने बाढ़ की तैयारी सुनिश्चित करने और आपातकालीन प्रतिक्रिया को सक्षम करने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। ये उपाय मानसून के मौसम में राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को निर्बाध यात्रा अनुभव प्रदान करने में सहायक सिद्ध होंगे।

आपदा की स्थिति से निपटने

........पृष्ठ 1 का शेष

जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदा राहत के मामले में भी तेजी लाये जाने की आवश्यकता है। इस आपदा में अब तक जो भी लोग प्रभावित हुए हैं उन्हें अति शीघ्र राहत और हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जाए। साथ ही प्रशासन से आग्रह है कि जिन स्थानों पर भी किसी प्रकार के खतरे की संभावना हो, उन्हें चिन्हित करके उसे खाली करवाया जाए। साथ ही प्रतिबंधित स्थानों पर स्थानीय लोगों और पर्यटकों को जाने से रोकने के समुचित प्रबंध किए जाएं। जयराम ठाकुर ने कहा कि मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि प्रभावित क्षेत्रों में यथाशीघ्र राहत कार्य करवाएं एवं पीड़ित परिवारों की उचित मदद करें। प्रदेशवासियों से भी मेरा विनम्र आग्रह है कि खराब मौसम के दृष्टिगत नदी-नालों व भूस्खलन संभावित क्षेत्रों के समीप जाने से बचें, सावधानी बरतें एवं सुरक्षित रहें।